

28.12.18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/पातेवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अपाथी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते नए केसि...
आगामी पेशी दिनांक
पेश हो (केस) 9.1.19

9.1.2019

राजपूताना व अर्वाची अधिवक्ता उप.।
नए केसि कुनी गर्डी, पत्रावली वास्ते केसि
दिनांक 16.1.2019 को पेश हो। (केस)

16.1.2019

पत्रावली वास्ते केसि पेश कुनी गर्डी
को अधिवक्ता - पत्र उठाना काराकी केसि इत तक
अंशद्वारा कुनी कुनी इत है कुनीवा केसि पाता है
विस्तृत केसि शाकिल पत्रावली ही T. D. Q. H. M. H.
को पालकाधिरा पाता पत्रावली केसि कुनी
ही

आदेश कुनीवा गर्डी

(केस)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :- राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 304/2015

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हनुमानगढ़।

---प्रार्थी

बनाम

मै० श्याम ईट उद्योग (निर्मला पत्नी सुरेशकुमार अग्रवाल) साकिन 20 एचएमएच।

---अप्रार्थी/खातेदार काशतकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थित :-

1. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित

प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 25/11/16

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काशतकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का भू-धारक है तथा भू-धारक की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 117/282 में कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 5/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है० भूमि है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काशतकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काशतकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य में संपरिवर्तन नहीं करवाया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईट भट्टा बना रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू-रूपांतरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काशतकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करवा प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत है, जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में बिना न्याय शुल्क के प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 117/282 में कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 5/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है० कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु अप्रार्थी ने उसको दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर ईट भट्टा स्थापित कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग

५

किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 117/282 में कि.न. 4/0.164, 5/0.139, 6/0.228, 7/0.253, 14/0.253, 15/0.253 कुल 1.290 है० कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि में से अप्रार्थी को बेदखल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के स्थान पर आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/1/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

u
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

